पंजा मत दिखाओ, इसने देश को गंजा कर दिया- भजनलाल

मुख्यमंत्री निवाई की सभा में एसआईआर व पेपर लीक पर सख्त तेवर में नज़र आए

टोंक/निवाई, 31 जनवरी (निस)। ग्राम उत्थान शिविर के काम काज को देखने शनिवार को निवाई आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं और राज्य सरकार को किसानों, महिलाओं और युवाओं के हमदर्द के रूप में पेश किया। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने प्रसिद्ध लोकोक्ति "जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई" का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें गरीब और किसान के हालात की समझ है, इसलिए केन्द्र की और उनकी सरकार लगातार उनके हित के लिए काम कर रही है।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान पेपर लीक करने वाले 45 लोगों को सरकार जेल में डाल चुकी है। यह कार्यवाही जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को टोंक जिले के निवाई में विकास कार्यों का शिलान्यास व वर्चुअल लोकार्पण किया। तथा मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता एवं राजीविका दीदी समूहों को प्रतीकात्मक रूप से चैक वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने भाषण की शुरूआत में जनसभा में उपस्थित लोगों को हाथ ऊपर कर भारत माता का जयकारा लगवाया। लोगों ने जब जयकारे के लिए हाथ ऊंचे किए तो मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि पंजा मत दिखाओ, इस पंजा ने देश को गंजा कर दिया है। उन्होंने कहा, पंजा खोलकर नहीं, मुट्ठी बांधकर जयकारे लगाओ। फिर मुख्यमंत्री ने पांच बार जयकारे लगवाए।

एसआइआर और पेपर लीक मामले में सख्त तेवर दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों प्रावधान देश और युवाओं के हित में हैं, इसलिए कोई समझौता नहीं होगा और गलत लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।

आम सभा के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने उनके शासनकाल में एक भी पेपर लीक नहीं होने का दावा करते हुए कहा कि पिछली सरकार के दौरान पेपर लीक करने वाले करीब 425 लोगों को सरकार जेल में डाल चुकी है। यह कार्रवाई जारी रहेगी। अपने भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा का नाम नहीं बदला है, बल्कि उसमें सुधार किया गया है।

जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों और महिलाओं को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने दो साल में विकास के इतने काम किए हैं कि उनकी सूची बनाई जाए तो पन्ने कम पड़ जाएंगे।

मोदी आदमपुर में गुरु रविदास हवाई अड्डे का नामकरण करेंगे

नयी दिल्ली, 31 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, महान संत और समाज सुधारक गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर रविवार को पंजाब का दौरा करेंगे और वहां आदमपुर हवाई अड्डे का नामकरण गुरु रविदास जी हवाई अड्डा, आदमपुर करने के साथ ही राज्य को नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे की सौगात देंगे।

- रविदास जयंति पर पंजाब दौरे में वे लुधियाना में टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे।

यहां जारी एक सरकारी विज्ञिप्त में यह जानकारी दी गयी। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी कल दोपहर करीब पौने चार बजे राज्य के आदमपुर पहुंचेंगे। मोदी अपने इस दौरे में लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। पंजाब में विमानन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में यह टर्मिनल भवन राज्य के लिए एक नया प्रवेश द्वार बनेगा, जिससे लुधियाना और आसपास के औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। लुधियाना जिले में स्थित हलवारा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारतीय वायु सेना केंद्र भी है।

उल्लेखनीय है कि लुधियाना के पुराने हवाई अड्डे का रनवे छोटा था, जो केवल छोटे विमानों की उड़ान के लिए उपयुक्त था। अब हलवारा में एक नया सिविल एन्क्लेव विकसित किया गया है, जिसका रनवे बड़ा है और यह ए320 जैसे बड़े विमानों के संचालन में सक्षम है।

दिल्ली पुलिस ने साइकोट्रॉपिक ड्रग्स रैकेट पकड़ा

पुलिस ने इस अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के तीन लोगों को गिरफ्तार किया

नयी दिल्ली, 31 जनवरी। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय साइकोट्रॉपिक ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 31 किलोग्राम अल्प्राजोलम टैबलेट्स बरामद की हैं। यह जानकारी शनिवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दी।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी एक संगठित गिरोह का हिस्सा थे, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रतिबंधित साइकोट्रॉपिक पदार्थों के अवैध निर्माण, परिवहन और आपूर्ति में संलिप्त था। दिल्ली पुलिस को एनसीआर में सक्रिय नशीले पदार्थों के तस्करों के बारे में खुफिया सूचना मिली थी, जिसके आधार पर निगरानी शुरू की गई।

अपराध शाखा के डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया, "गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने नंद नगरी बस डिपो के पास उत्तर प्रदेश नंबर की एक कार को रोका और उसमें सवार तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया।" गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शमीम (निवासी: बदायूं, उत्तर प्रदेश), राजीव शर्मा और मोहित गुप्ता (दोनों निवासी: बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है।

- पुलिस ने कहा, आरोपी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश व दिल्ली में प्रतिबंधित साइकोट्रॉपिक दवाएं बनाते थे।

तलाशी के दौरान पुलिस ने 31 किलोग्राम अल्प्राजोलम टैबलेट्स बरामद कीं, जिनकी संख्या करीब तीन लाख गोलियां बताई जा रही है। यह मात्रा एनडीपीएस एक्ट के तहत वाणिज्यिक श्रेणी में आती है।

डीसीपी ने बताया कि अल्प्राजोलम के लिए वाणिज्यिक मात्रा की सीमा 100 ग्राम है। इसके अलावा, पुलिस ने 11 किलोग्राम अल्यूमिनियम फॉयल, जिस पर अल्प्राजोलम मुद्रित था, 25 किलोग्राम पीवीसी शीट रोल, जो पैकेजिंग में इस्तेमाल होते थे, 20 रबर स्टैंप, जिन पर बैच नंबर, निर्माण और समाप्ति तिथि अंकित थी, तथा तस्करी में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त की है।

पूछताछ के दौरान राजीव शर्मा ने कथित तौर पर बताया कि वह मोहित गुप्ता के निर्देश पर काम करता था और हिमाचल प्रदेश से शमीम व उसके सहयोगी रंदीप से अल्प्राजोलम टैबलेट्स लेकर उन्हें बुलंदशहर की स्थानीय फार्मेसियों में सप्लाई करता था।

वहीं, शमीम ने पुलिस को बताया कि वह अपने साथी के साथ परवाणू (हिमाचल प्रदेश) में एक अवैध निर्माण इकाई चला रहा था, जहां से टैबलेट्स बनाकर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वितरकों को सप्लाई की जाती थीं।

पुलिस के मुताबिक, मोहित गुप्ता, जो बुलंदशहर में एक मेडिकल फर्म चलाता है, उसने जांचकर्ताओं को बताया कि वह अपनी फर्म के जरिए अवैध टैबलेट्स खरीदता था और उन्हें आगरा व बुलंदशहर की फार्मेसियों में सप्लाई करता था। डीसीपी विक्रम सिंह ने कहा, "मामले की आगे की जांच जारी है।"

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री, जी. परमेश्वर ने पार्टी अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की

बेंगलुरु, 31 जनवरी। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने शनिवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से शिष्टाचार मुलाकात की। यह मुलाकात मुख्य रूप से विकास संबंधी मुद्दों पर केंद्रित थी।

हालांकि, यह मुलाकात राज्य में अगले मुख्यमंत्री पद की दौड़ को लेकर मीडिया में चल रही अटकलों के बीच हुई है, जिसमें मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्दारमैया का मुकाबला उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से है। परमेश्वर ने इस मुलाकात को सौहार्दपूर्ण और व्यक्तिगत बताया और इसे "पारिवारिक" मुलाकात कहा। उन्होंने कहा कि चर्चा पेयजल की कमी और बजट प्रावधानों जैसी राज्य की चिंताओं पर केंद्रित थी और इसमें राजनीतिक मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई। राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सरकार के आधे कार्यकाल के पूरा होने पर कांग्रेस नेतृत्व पर आंतरिक नेतृत्व संबंधी अटकलों को सुलझाने का दबाव बढ़ रहा है। वरिष्ठ नेता कथित तौर पर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या शिवकुमार को सिद्दारमैया के बाद अगला मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए।

इन अटकलों के बावजूद शिवकुमार ने दोहराया है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद संभालने की कोई जल्दी नहीं है और वे पार्टी हाई कमांड के फैसले का पालन करेंगे। वहीं सिद्दारमैया ने भी इस बात पर जोर दिया है कि नेतृत्व का फैसला केंद्रीय कमान के हाथ में है, और इस बात को रेखांकित किया कि अटकलों के बीच दोनों नेता एकजुट हैं। पर्यवेक्षकों का मानना है कि परमेश्वर की टिप्पणियों और इन मुलाकातों के दौरान उनके रुख पर बारीकी से नजर रखी जाएगी, क्योंकि ये राज्य के सर्वोच्च पद की दौड़ में चल रही व्यापक रणनीतिक गणनाओं को प्रभावित कर सकती हैं।

छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ 1 फरवरी से

रायपुर, 31 जनवरी। छत्तीसगढ़ की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में प्रसिद्ध राजिम एक बार फिर सनातन परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनने जा रहा है। माघ पूर्णिमा 1 फरवरी से महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले राजिम कुंभ कल्प 2026 का भव्य आयोजन इस वर्ष भी नए मेला स्थल चौबेबांधा, राजिम में किया जाएगा।

- यह वृहद् धार्मिक कार्यक्रम महाशिवरात्रि, 15 फरवरी तक चलेगा।

कुंभ कल्प का शुभारंभ माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका के करकमलों से करेंगे। राजिम कुंभ कल्प के शुभारंभ अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिष्ठित संत-महात्माओं का आगमन होगा।

कश्मीर घाटी में अभी और बर्फ गिरने की संभावना

श्रीनगर, 31 जनवरी। मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में आगामी दिनों में रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, कश्मीर में अगले कुछ दिनों के दौरान कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेंगे। उल्लेखनीय है कि कश्मीर घाटी में चिल्लई कलां, यानी सर्दियों के सबसे कठोर 40 दिनों के दौरान दो बार अच्छी बर्फबारी दर्ज की गयी थी। चिल्लई कलां शुक्रवार को समाप्त हो गया।

एनजीटी ने यमुना नदी में प्रदूषण रोकने के सख्त निर्देश दिये

शिमला, 31 जनवरी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पानी की बिगड़ती गुणवत्ता, जलीय जीवन और नदी के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों को यमुना नदी में प्रदूषण को रोकने के लिये निगरानी और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया है।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 16-पृष्ठ के विस्तृत आदेश में एक मूल आवेदन का निपटारा करते हुए राज्यों को 10 विशिष्ट निर्देश जारी किए। इसमें उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक कचरे को बहाये जाने की जांच करने और अनुपचारित कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकने में केंद्रीय एजेंसियों की सहायता करने के उपायों की रूपरेखा तैयार की गयी है।

- ये निर्देश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ प्रमुख केन्द्रीय एजेंसियों को दिए गए हैं।

एनजीटी एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर शुरू किये गये स्वत: संज्ञान आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें यमुना में देशी मछली प्रजातियों में भारी गिरावट और प्रदूषण-सहिष्णु विदेशी प्रजातियों में इसी तरह की वृद्धि पर प्रकाश डाला गया था।

मोदी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पत्नी सुनेत्रा पवार ने आज शाम ही महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे अपने पति दिवंगत अजित पवार के स्थान पर फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं। पवार राज्य मंत्रिमंडल में उपमुख्यमंत्री थे। उनका 28 जनवरी को बारामती में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। उपमुख्यमंत्री रहते हुए पवार के पास वित्त, खेल, आबकारी जैसे मंत्रालय थे।

पहली बार जनप्रियता नहीं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऐसे कदम यह साफ़ करेंगे कि मोदी सरकार अब भी राज्य-प्रेरित विस्तार (स्टेट-ड्रिवन एक्सपैन्शन) के बजाय, बाज़ार आधारित विकास (मार्केट लैड ग्रोथ) के पक्ष में है। पूंजी और ट्रेडिंग पर टैक्स का बोझ कम करके सरकार का मक़सद लिक्विडिटी को बढ़ाना, बाज़ार की गहराई सुधारना और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) को आकर्षित करना है, जिनका प्रवाह अब वैश्विक ब्याज दरों और नीतिगत स्थिरता को लेकर ज़्यादा संवेदनशील हो गया है।

हालांकि, सुधारों पर जोर देने के साथ-साथ, राजनीतिक गणनाएं भी चल रही हैं। इस साल पाँच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में केन्द्र से होने वाला खर्च चुनावी भूगोल को ध्यान में रखकर तय किए जाने की उम्मीद है।

इन चुनावी राज्यों में बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण योजनाओं और रोज़गार से जुड़े कार्यक्रमों पर बढ़ा हुआ खर्च प्रमुख रूप से सामने आ सकता है। इससे सरकार विकास-केन्द्रित शासन की छवि पेश करते हुए अपनी राजनीतिक पकड़ भी मज़बूत करना चाहती है।

यह दोहरी रणनीति, केन्द्र में बाज़ार को खुश करना और राज्यों में लक्षित खर्च सरकार की सुधारवादी महत्वाकांक्षा को चुनावी व्यावहारिकता के साथ संतुलित करने के प्रयास को उजागर करती है।

आलोचकों का कहना है कि इस तरह की चुनिंदा उदारता से वित्तीय प्राथमिकताएं बिगड़ सकती हैं, जबकि समर्थकों का तर्क है कि असमान रिकवरी के दौर में क्षेत्रीय प्रोत्साहन, मांग को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। वित्तीय अनुशासन एक और महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है।

वैश्विक रेटिंग एजेंसियां और बॉन्ड बाज़ार भारत के घाटे और कर्ज़ की स्थिति पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। ऐसे में सरकार के पास खुले तौर पर लोकलुभावन नीतियों के लिए सीमित गुंजाइश है। किसी भी विस्तारवादी कदम के साथ घाटा कम करने, परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण (एसैट मॉनटाइज़ेशन) और टैक्स कंप्लायंस बेहतर करने के ठोस वादे भी ज़रूरी होंगे।

टैक्सेशन के अलावा, बजट से मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात एजेंडे को भी मजबूत करने की उम्मीद है, खासकर तब, जब वैश्विक कंपनियां सप्लाई चेन को चीन से दूर ले जाकर विविधता लाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि सिर्फ़ प्रोत्साहन काफ़ी नहीं होंगे, नियामक स्पष्टता, अनुबंधों का प्रभावी क्रियान्वयन और विवादों का तेज़ समाधान ही भू-राजनीतिक अवसरों को वास्तविक निवेश में बदल पाएगा।

आख़िरकार, मोदी 3.0 का दूसरा बजट बड़े और चौंकाने वाले ऐलानों से ज़्यादा रणनीतिक संकेत देने वाला होगा। यह बताएगा कि क्या सरकार चुनावी दबावों और वैश्विक अनिश्चितता के बीच निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए गहरे आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता देने को तैयार है। ऐसा करके यह बजट, मोदी 3.0 के सामने खड़े एक बुनियादी सवाल का भी जवाब देगा, पहले बाज़ार या पहले मतदाता, या फिर दोनों का सोच-समझकर तैयार किया गया मिश्रण।

क्या एनसीपी के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा, "हमें शपथ ग्रहण के बारे में कुछ नहीं पता। हमें इसकी जानकारी समाचारों से मिली।

मुझे शपथ ग्रहण के बारे में कोई जानकारी नहीं है।"

उन्होंने बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कही, जब उनसे यह पूछा गया कि क्या पवार परिवार का कोई सदस्य समारोह में शामिल होगा।

एनसीपी (एसपी) नेता अंकुश काकड़े ने दावा किया कि अजित पवार अपने जन्मदिन (12 दिसंबर) पर चाचा शरद पवार को पुनर्मिलन का 'तोहफ़ा' देना चाहते थे, लेकिन उस समय यह विलय आकार नहीं ले सका।

काकड़े के अनुसार, अजित पवार ने उनसे और अन्य वरिष्ठ नेताओं, जिनमें विठ्ठल शेठ मणियार और श्रीनिवास पाटिल शामिल थे, जो वरिष्ठ पवार के क़रीबी माने जाते हैं, से सुलह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आग्रह किया था।

काकड़े ने जूनियर पवार के शब्दों को याद करते हुये कहा, "आपके साहेब (शरद पवार) से अच्छे संबंध हैं; कृपया उनसे बात करें। यह देखने की कोशिश करें कि एनसीपी के दोनों गुट किस तरह फिर से एक हों।

एनसीपी (एसपी) नेता ने कहा, "अजित पवार ने मुझसे कहा था कि हमें 12 दिसंबर को एक होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कोई बात नहीं, हम चुनावों के बाद साथ आ जाएँगे। दुर्भाग्यवश, वे अपनी यह इच्छा पूरी नहीं कर सके।"

सूत्रों के अनुसार, शरद पवार और अजित पवार ने 17 जनवरी को पार्टी के संभावित पुनर्मिलन पर चर्चा के लिए मीटिंग की थी। दोनों ने 12 फरवरी को इस पुनर्मिलन की घोषणा करने का निर्णय लिया था।

जब पुनर्मिलन के बारे में पूछा गया, तो वरिष्ठ पवार ने कहा कि चर्चा के दौरान अजित पवार और जयंत पाटिल मौजूद थे, और अब इस पर अंतिम फ़ैसला पाटिल लेंगे।

'फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो'

भाजपा ने आरोप लगाया कि प.बंगाल सरकार इस अग्निकांड के आरोपियों को बचा रही है

नयी दिल्ली, 31 जनवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल सरकार पर कोलकाता के पास आनंदपुर में वॉव मोमो के गोदाम में आग लगने की घटना के लिए जिम्मेदार बड़े लोगों को बचाने का आरोप लगाते हुए घटना की उच्चतम न्यायालय की निगरानी जांच कराये जाने की शनिवार को मांग की।

भाजपा ने कहा कि अकेले जनवरी में पश्चिम बंगाल में कम से कम पांच जगहों पर विभिन्न फैक्ट्रियों में आग लगने की घटनाएं हो चुकी है जो दर्शाती है जो राज्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्निशमन और बचाव के नियमों का अनुपालन नहीं कराया जा रहा है।

- भाजपा ने कहा कि इस फैक्ट्री वॉव मोमो के प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी हैं।
- ज्ञातव्य है कि इस अग्निकांड में 27 मजदूरों की मौत हुई है।

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरुप्रकाश ने भाजपा मुख्यालय पर एक संवाददाता सम्मेलन में खबरों का हवाला देते हुए कहा कि आनंदपुर फैक्ट्री दुर्घटना में कम से कम 27 गरीब और मेहनतकश लोगों की जान चली गयी और बहुत से लोग लापता हैं। उन्होंने इस दुर्घटना को भीषण और वीभत्स बताते हुए कहा कि वॉव मोमो के प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नजदीकी है इसलिए राज्य सरकार इस पर चुप है। फैक्ट्री के गोदाम मैनेजर और एकाध निचले स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की खानापूर्ति कर इतनी बड़ी घटना पर सरकार चुप लगा गयी है।

भाजपा मीडिया में प्रकाशित एक सचित्र रिपोर्ट को दिखाते हुए कहा कि वॉव मोमो के प्रमुख मुख्यमंत्री के करीब है और वह उनकी मैड्रिड यात्रा में उनके साथ थे। उन्होंने कहा, राज्य में कानून नहीं, एक व्यक्ति का शासन है। आनंदपुर फैक्ट्री दुर्घटना पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है।

अचानक क्यों बदला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्या यह सीट सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को दी गई?

हालाँकि तीन लंबित सीटों की अभी घोषणा कर दी गई है, लेकिन एक सीट अब भी घोषित और तय नहीं हो पाई है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की ज़िद के कारण।

राजसमंद के ज़िला अध्यक्ष का पद अब भी लंबित है, क्योंकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी अपनी पसंद के व्यक्ति की नियुक्ति चाहते हैं। जोशी चाहते हैं कि आदित्य प्रताप सिंह, जो एक राजपूत नेता हैं, को यह पद दिया जाए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने उन्हें ज़िला का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कराया था।

समस्या यह है कि दोनों ओर की दो पड़ोसी सीटों-प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, में पहले से ही राजपूत ज़िला अध्यक्ष हैं, जबकि पार्टी यहाँ ओबीसी चेहरे को आगे बढ़ाकर ओबीसी समुदाय को एक मज़बूत संदेश देना चाहती है।

लेकिन एक व्यक्ति की ज़िद के कारण यह पद अब तक लंबित पड़ा है।

दिलचस्प बात यह है कि पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा इस मामले में, और राजस्थान से कांग्रेस को मिलने वाली एकमात्र राज्यसभा सीट के मामले में भी, सी. पी. जोशी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं।

- आजकल डोटासरा सी.पी. जोशी के साथ हैं, क्योंकि दोनों इस वक्त अशोक गहलोत विरोधी हैं।
- प्रारंभ में सी.पी. जोशी गहलोत विरोधी थे, पर, गहलोत के मु.मंत्री बनने पर वे गहलोत समर्थक हो गए थे और अब वो पुनः डोटासरा की भांति गहलोत विरोधी हैं।
- प्रभारी रंधावा भी इसी "रोड मैप" पर चल रहे हैं, क्योंकि वे प्रदेशाध्यक्ष के बनाये रास्ते पर ही चलना उचित समझते हैं।
- इन मौसम की तरह बदलते समीकरणों में, यह कहना इतना आसान नहीं कि क्यों और कैसे जिलाध्यक्ष नियुक्त हो रहे हैं, पर, एक मूल सत्य यह है कि जिसने जितनी बड़ी बोली लगाई उसकी नियुक्ति की संभावना प्रबल होती जाती है।

कारण सीधा है, सत्ता में कौन है, इसके अनुसार नेताओं के बीच समीकरण बदलते हैं और यह लगभग आम होता जा रहा है।

वर्तमान में डोटासरा और जोशी- दोनों ही अशोक गहलोत के खिलाफ़ है। गहलोत ने ही डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष पद तक पहुँचाया, जो आज वे हैं, बनाया। सी. पी. जोशी पहले गहलोत विरोधी थे, फिर जब गहलोत मुख्यमंत्री बने तो उनके समर्थक हो गए, और अब वे फिर से गहलोत विरोधी हो गए हैं।

रंधावा ने भी वही रास्ता अपनाया है और अब वे पूरी तरह डोटासरा के साथ खड़े हैं, और दोनों जाट हैं।

आने वाले दिनों में ऐसे कई और समीकरण सामने आएँगे।

अमेरिका यूएन (संयुक्त राष्ट्र संघ) को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपने मूल तंत्र को चलाए रखने के लिए आकलित योगदानों, सदस्य देशों द्वारा दिए जाने वाले अनिवार्य शुल्क, पर निर्भर करता है। इसके कार्यों में प्रमुख हैं: शांति स्थापना की निगरानी, मानवीय समन्वय, राजनीतिक मध्यस्थता, मानवाधिकार निगरानी और विकास समर्थन। जब सबसे बड़ा योगदानकर्ता भुगतान रोक लेता है, तो व्यवस्था केवल धीमी ही नहीं पड़ती, बल्कि वह जाम होने लगती है।

संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि पूंजी की कमी पहले से ही कठिन फैसले लेने को मजबूर कर रही है, जैसे कर्मचारियों और विक्रेताओं को भुगतान में देरी, मिशनों का सीमित होना, मानवीय तैनाती का स्थगन, और संकटों के लिए रखे गए आपात भंडार का क्षरण। वस्तुत: दुनिया की एकमात्र सार्वभौमिक बहुपक्षीय संस्था से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह उधार पर काम करे, जबकि दुनिया भर में उसकी सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है।

यह हिसाब-किताब की कोई अमूर्त समस्या नहीं है। यह तो ऐसे समय में हो रहा है, जब संघर्ष बढ़ रहे हैं, जलवायु की समस्या तीव्र हो रही है, दुनिया भर में भूख बढ़ रही है, और विस्थापन रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुका है। गाज़ा से सूडान तक, हैती से म्यांमार तक, संयुक्त राष्ट्र अक्सर आख़िरी कार्यशील अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति होता है, जो सहायता का समन्वय करता है, नाज़ुक युद्धविरामों में मध्यस्थता करता है तथा, जब कोई और नहीं करता, तो अत्याचारों का दस्तावेज़ीकरण भी करता है।

गरीब देशों के लिए तो इसके निहितार्थ विशेष रूप से गंभीर हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से खाद्य सहायता देती है, यूएनएचसीआर के ज़रिये शरणार्थियों की मदद करती है, डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व में स्वास्थ्य कार्यक्रम और यूएनडीपी के माध्यम से विकास वित्त का समन्वय करती है। संयुक्त राष्ट्र की क्षमता में कोई भी कटौती सबसे पहले और सबसे अधिक निम्न आय वाले देशों को प्रभावित करती है, क्योंकि उनके पास वैकल्पिक सुरक्षा तंत्र नहीं होता।

कई संवेदनशील देशों में, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ अनुपस्थित या ढह चुकी राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभावी विकल्प बन जाती हैं। वे वैक्सीन पहुँचाती हैं, शरणार्थी शिविरों में स्कूल चलाती हैं, चुनाव निगरानी का समर्थन करती हैं, और सरकारों को ऋण प्रबंधन, जलवायु अनुकूलन तथा संघर्षोत्तर पुनर्निर्माण में मदद करती हैं। जब फंड नहीं मिलता, तो ये जीवनरेखाएँ पतली पड़ जाती हैं या पूरी तरह गायब हो जाती हैं।

इस संकट में एक गहरा भू-राजनीतिक संकेत भी निहित है। अमेरिका द्वारा अपने संयुक्त राष्ट्र दायित्वों को पूरा न करना केवल संगठन की वित्तीय स्थिति को ही नहीं, बल्कि उसकी नैतिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक सुसंगतता को भी कमज़ोर करता है। वॉशिंगटन लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र को नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का स्तंभ बताता आया है। लगातार भुगतान न करना इस दावे को कमजोर करता है और अन्य देशों को भी अपने दायित्वों में देरी या कटौती के लिए प्रोत्साहित करता है।

उभरते और गरीब देशों के लिए यह क्षरण महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र उन गिने-चुने मंचों में से एक है, जहाँ छोटे राज्यों की आवाज़ लगभग बड़ी शक्तियों के बराबर होती है। वित्तीय रूप से कमजोर संयुक्त राष्ट्र कम स्वतंत्र, अधिक दाता-निर्भर और सीमित संख्या में अमीर या रणनीतिक रूप से प्रेरित राज्यों के दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है।

एक रणनीतिक शून्य का जोखिम भी है। जैसे-जैसे पश्चिमी फंडिग कमज़ोर पड़ती जा रही है, अन्य शक्तियाँ चयनात्मक रूप से आगे आ सकती हैं, राजनीतिक निष्ठा से जुड़ी सहायता की पेशकश करते हुए, न कि सार्वभौमिक मानदंडों के आधार पर। इससे वैश्विक शासन के प्रतिस्पर्धी गुटों में विखंडन तेज़ हो सकता है, एक ऐसा विकास, जो उन गरीब देशों को असमान रूप से नुकसान पहुँचाता है, जो महान शक्तियों के संरक्षण के बजाय तटस्थ बहुपक्षीय ढाँचों पर निर्भर रहते हैं।

इसलिए महासचिव की चेतावनी बैलेंस शीट की बजाय, विश्वसनीयता से अधिक जुड़ी है। स्थायी किफ़ायत में धकेला गया संयुक्त राष्ट्र न तो प्रभावी ढंग से युद्धों में मध्यस्थता कर सकता है, न जलवायु कार्रवाई का समन्वय कर सकता है, और न ही महामारियों का जवाब दे सकता है। बजट कटौती से खोखली हो चुकी निगरानी व्यवस्थाओं के साथ वह अंतरराष्ट्रीय क़ानून को भी कायम नहीं रख सकता।

दुनिया की सबसे गरीब आबादी के लिए खतरा कई गुना है। कम शांति सैनिकों का मतलब अधिक अस्थिरता। मानवीय सहायता में देरी का मतलब अधिक मृत्यु दर। विकास समन्वय में कमी का मतलब झटकों से उबरने की धीमी गति, चाहे वे आर्थिक हों, जलवायु संबंधी हों या राजनीतिक।

ऐसे समय जब विश्व में असमानता बढ़ रही है और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में भरोसा पहले ही कमज़ोर पड़ता जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र में वित्तीय आपदा यह नुकसानदेह संदेश देगी कि सामूहिक समस्या-समाधान वैकल्पिक है, और विश्व सार्वजनिक हितों को तब तक हल्के में लिया जा सकता है, जब तक वे विफल न हो जाएँ।

विडंबना यह है कि संयुक्त राष्ट्र के मूल कार्यों को बनाए रखने की लागत, अनियंत्रित संघर्ष, अव्यवस्थित प्रवासन, महामारियों या जलवायु आपदाओं की कीमत की तुलना में नगण्य है। फिर भी, विशेषकर अपने सबसे बड़े योगदानकर्ता से फंड नहीं मिलने से संगठन को पक्षाघात की ओर धकेला जा रहा है।

अत: दांव पर केवल संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिरता नहीं है, बल्कि बहुपक्षवाद का भविष्य ही है। गरीब देशों के लिए, संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय नींव का ढहना ऐसी दुनिया का संकेत होगा, जो कम सहयोगी, कम पूर्वानुमेय और कहीं अधिक कठोर होगी, ठीक उसी समय, जब वे इसे वहन करने में सबसे कम सक्षम होंगे।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा। आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908